Regional Supplement of Punjab Kesari, Delhi

उत्तर प्रदेश केसरी

पृष्ठ संख्या 12+4+4=20

26 जून, 2013 बुधवार

लखनऊ केसरी

पहली नजर

गांधी भवन में उप्र माध्यमिक शिक्षा संघ द्वारा आयोजित शैक्षिक विचार गोष्ठी में भाग लेते अतिथिगण।

व्यापार कर विभाग ने पकड़े पांच ट्रक

लखनऊ,(ब्यूरो):व्यापारकर विभाग के सचल दल ने भोर में कानपुर रोड व फैजाबाद रोड पर अभियान चलाकर पांच ट्रक पकड़े। इस पर पाण्डेयगंज, यहियागंज थोक मार्केट से सामान लादकर गैर जनपदों को भेजा जा रहा था। माल का पेपर न दिखा पाने के कारण सचल दस्ता ट्रकों को कार्यालय ले आया। चेकिंग के दौरान फैजाबाद रोड पर से 3 तथा कानपुर रोड से 2 ट्रक पकड़े गए। इन ट्रकों से परचून का सामान गोण्डा व उन्नाव भेजा जा रहा था। ट्रक चालक ने जो कागज दिखाए उनपर माल कम दर्ज है जबकि गाड़ी में माल अधिक था। इस आधार पर जांच दल ट्रकों को नरही स्थित व्यापारकर मुख्यालय ले आया। सोमवार को ट्रकों की जांच नहीं हो पायी थी। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि जांच के बाद ही वास्तविक स्थिती सामने आएगी।

गौ सेवा आयोग अध्यादेश की अधिसूचना जारी

लखनऊ,(असलम सिद्दीकी): उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है। इस अध्यादेश से मूल अधिनियम 1999 की धारा (4) में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार पशुपालन विभाग का प्रमुख सचिव, सचिव पदेन सदस्य होगा एवं उपाध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी बनाये जाएगें। इससे संबंधित अधिसूचना विधायी विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी कर दी गयी है।

दुकानों में फायरिंग के मामले में चार गिरफ्तार

लखनऊ,(ब्यूरो):राजधानी के वजीरगंज के गौसनगर मोहल्ले में हुयी दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर दो-दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक पक्ष रास्में रोक मारने-पीटने का तो दूसरा पक्ष हलवाई की दुकान पर आकर मारपीट करने का आरोप लगा रहा है। वजीरगंज थानान्तर्गत 193,56, गौसनगर निवासी सुहेल हैदर ने रिपोर्ट दर्ज करायी है, जिसमें उसने कहां कि वह स्कूटर से चार साल के भांज के साथ जा रहा था, तब उसे रास्ते में रोककर उजैर आसिफ व फैजी ने मारापीटा। वह अपने भांजे के साथ जान बचाकर भागा और गोलागंज मकबरे में छिपकर जान बचायी।

इस मामले में पुलिस ने नई बस्ती पत्थर वाली गली निवासी मो. सलीम व बारुदखाना गोलागंज निवासी फैजी कान को गिरफ्तार किया है। इसी तरह दूसरे पक्ष से बागशेरजंग वजीरगंज में हलवाई की दुकान चलाने वाले मो. इस्माइल ने दी गयी तहरीर में आरोप लगाया कि वह दुकान पर बैठा था, तभी 8-10 लोग आये और गाली-गलौज कर उसे व कारीगरों को पीटने लगे। पिटाई करने वालों में अमान जाफरी, अज्जू, रिक्कू व मिशम शामिल थे। पुलिस ने आरोपित अमान जाफरी व अज्जू उर्फ सुहेल को सोमवार को सम्राट टेंट हाउस के पास से गिरफ्तार करने में सफलता पायी है। विदित हो कि शनिवार को गांसनगर वजीरगंज में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। इसी को लेकर कुछ लोगों के बीच रविवार को फिर मारपीट हुई थी, जिसमें हमलावरों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ व हवाई फायरिंग की थी।

आज से मिलनी शुरु होगी इंटर की मार्कशीट

लखनऊ,(ब्यूरो):उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा अंक पत्र बुधवार से बंटने शुरू हो जाएंगें। परिषद की ओर से अंक पत्र शिक्षा भवन भेज दिया गया है। राजधानी में यूपी बोर्ड के लगभग छह सौ कालेज हैं जहां इंटर की पढ़ाई होती है।

लोकदल करेगा विधान भवन का घेराव

जनसमस्याओं को लेकर खोला मोर्चा: सरकार नहीं चेती तो होगा जेल भरो आंदोलन

लखनऊ,(असलम सिद्दीकी): उत्तराखंड की आपदा में केंद्र व प्रदेश सरकार की हीलाहवाली, उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, बिजली, पानी जैसी तमाम मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए लोकदल 26 जून को विधानसभा का घेराव करेगा, इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। यह बात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उत्तरांचल में आई आपदा को न तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा मान रही है और न ही यहां पर सही तरीके से राहत कार्य किए जा रहे हैं। सेना को छोड़कर अन्य प्रशासनिक मशीनरी सुस्त है और दोनों प्रमुख दल राजनीति कर रहे हैं। नागरिक उड्डयन विभाग को चाहिए था कि वह अन्य विमानों का अधिग्रहण करता और उसे उत्तरांचल में लगा देता। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राहत में सुस्ती दिखाई है। उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चंद जिलों को छोड़कर अन्य जिलों को कुछ ही घंटे बिजली मिल रही है जबकि किसानों को महज चार घंटे ही बिजली मिल पा रही है। बेरोजगारों को भत्ता देकर उनका अपमान किया जा रहा है जबकि इसी राषि से रोजगार सृजित किए जाते तो सभी का भला होता। इसी तरह जहां सदन के अंदर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह चीन की नीति और चीन का विरोध करते हैं तो पूरे प्रदेष के बच्चों को चाइना निर्मित लैपटाप बांटे जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर लोकदल 26 जून को विधानसभा का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो वह जेल भरो आंदोलन करेंगे। इस मौके पर प्रदेष अध्यक्ष मृगेंद्र पांडे, राजवीर सचान आदि उपस्थित रहे।

उत्तराखंड की आपदा में केंद्र व प्रदेश सरकार की हीलाहवाली

सेना को छोड़कर अन्य प्रशासनिक मशीनरी सुस्त

किसानों को महज चार घंटे ही बिजली

लखनऊ के लोकदल कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह। (छाया :पंजाब केसरी)

नगर निगम के कर्मचारियों ने दिया एक दिन का वेतन

लखनऊ,(ब्यूरो):महापौर डा.दिनेश शर्मा की मौजूदगी में नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन उत्तराखण्ड के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए देने का एलान किया। पार्षद भी उत्तराखण्ड के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने भी एक दिन का वेतन देने की घोषणा की। महापौर डा.दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों व पार्षदों की बैठक हुई। इसमें तृतीय श्रेणी तक के सभी कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन देने की हामी भरी। कई पार्षदों ने महापौर के समक्ष ही सहयोग राशि नगर निगम कोष में जमा करायी। उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने भी महापौर व नगर आयुक्त से मिलकर एक दिन का वेतन उत्तराखण्ड के पीड़ितों के लिए देने का सहमति पत्र प्रदान किया।

उत्तराखण्ड में प्रदेश सरकार ने लगाए राहत शिविर

लखनऊ, (अरविन्द):उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा में प्रभावित हुए लोगों के लिए जौलीग्रान्ट , ऋषिकेश तथा हरिद्वार में राहत शिविर आरंभ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन राहत शिविरों को समन्वित तरीके से चलाए जाने के निर्देश दिए हैं जिससे कि लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इन राहत शिविरों को और भी सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है तथा यहां पर चिकित्सा, चाय, पूड़ी-सब्जी, गद्दों, कुर्सियों की सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रमुख सचिव गृह आर एम श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रभावित व्यक्तियों के लिए शिविरों मे फोन की भी व्यवस्था की गई है जिससे कि वे अपने परिजनों से सम्पर्क कर सकें। शिविरों में आपदा से प्रभावित हुए देश के सभी राज्यों के लोगों को सुविधाए दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों को बसों से निशुल्क ले जाने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि गंगा, यमुना के किनारे बसे जिलों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को अलर्ट जारी किया गया है कि इन नदियों में बहते हुए शवों को एकत्रित कर उनकी शिनाख्त के हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके लिए उन शवों के फोटोग्राफऔर डीएनए टेस्ट के लिए नमूने रखे जाने चाहिए। शवों का अन्तिम संस्कार गरिमामय तरीके से सरकारी खर्च पर किया जाएगा।

चिकित्सा, चाय, पूड़ी-सब्जी, गद्दों, कुर्सियों की सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई

उत्तराखण्ड राज्य में दैवीय आपदा में प्रशासकीय सहयोग के लिए राज्य सरकार ने सिटी मजिस्ट्रेट बांदा अनिल कुमार व सिटी मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद उदय सिंह , उपजिलाधिकारी बिजनौर आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ,उपजिलाधिकारी मथुरा रमेश चन्द्र ,उपजिलाधिकारी कानपुर नगर कामता प्रसाद सिंह , सहायक भूलेख अधिकारी हापुड़ कपिल सिंह आदि अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। ये अधिकारी कार्यमुक्त होकर प्रमुख सचिव गृह उत्तराखण्ड शासन देहरादून को योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

सांसदों, मंत्रियों व जनता से भी की सहयोग करने की अपील

लखनऊ, (अरविन्द,असलम): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों एवं राज्य की जनता के सामने अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उत्तराखण्ड में आई दैवीय आपदा में प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए अपना एक माह का वेतन देने का निर्णय लिया है। यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के मंत्रियों तथा समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों तथा विधायकों से भी उत्तराखण्ड में आई दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए योगदान देने की अपील की है। उन्होंने राज्य की जनता तथा संगठनों से 'मुख्यमंत्री राहत कोष' में अधिक से अधिक ऐच्छिक सहयोग प्रदान करने की भी अपील की है। उत्तराखण्ड को पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए अधिक राशि की आवश्यकता होगी। इस दैवीय आपदा से निपटने के लिए देशवासियों को बढ़-चढ़ कर उत्तराखण्ड सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए। राज्य की जनता तथा अन्य संगठन अपना सहयोग 'मुख्यमंत्री राहत कोष' में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सुनील कुमार पाण्डेय, उपसचिव मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ को भेज सकते हैं।

मुख्यमंत्री अखिलेश ने उत्तराखण्ड के पीड़ितों की मदद के लिए दिया एक माह का वेतन

बारावफात के अवसर पर लखनऊ स्थित महानगर काब्रिस्तान में अपने परिचितों की कब्र पर रौशनी करते मुस्लिम समाज के लोग।(छाया: पंजाब केसरी)

लविवि में 2010 के पूर्व नियुक्त कर्मचारी होंगे स्थायी

लखनऊ,(ब्यूरो):लखनऊ विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की समस्या को लेकर कुलसचिव अमिताभ प्रकाश ने वित्त अधिकारी और सहायक कुलसचिवों के साथ सोमवार को बैठक कर समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। बैठक में कर्मचारियों के पांच मुख्य मांगें रखी थी। अधिकतर समस्याओं के निराकरण पर सहमति बन गयी है। बैठक में 29 जून 1991 के पहले नियुक्त अनानुमोदित कर्मचारियों के विनियमितीकरण, वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के स्थायीकरण और कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ शामिल है। बैठक के बाद लविवि कर्मचारी परिषद के महामंत्री संजय शुक्ल ने कुलपति डा. एसबी निमसे और कुलसचिव अमिताभ प्रकाश को धन्यवाद देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांग काफी समय से लंबित थी लेकिन उनकी समस्या को देखते हुए कुलपति और कुलसचिव ने पहल की है। संजय शुक्ल ने बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह में भी एक बैठक आयोजित जाएगी। कर्मचारियों की मांग शासन भेजा जाएगा। शासन से अनुममित मिलने के बाद इसको कार्य परिषद में पास कर दिया जाएगा।

राजधानीवासियों ने भेजी 15 ट्रक राहत सामग्री

लखनऊ,(ब्यूरो):उत्तराखण्ड में आयी आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए बड़ों के साथ ही बच्चे भी आगे आ गए हैं। तमाम बच्चों ने चाकलेट, टाफी, आइसक्रिम पर होने वाले रोज के खर्च में से पैसे निकालकर माता-पिता के साथ जाकर सहायता शिविर में जमा किए। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों से सोमवार को महापौर डा. दिनेश शर्मा ने 15 ट्रक रसद रवाना किया । इसके अलवा अन्य संगठनों ने भी ट्रक रवाना किया। लोगों का कहना है कि यह मदद केवल वहां फंसे लोगों के लिए ही नहीं बल्कि इस आपदा में अपना सब कुछ गवां चुके स्थानीय नागरिकों के लिए भी भेजी जा रही है। संकट की इस घड़ी में लखनऊ की जनता उनके साथ है। उधर वहां फंसे लोगों की सलामती व मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुआएं की गयीं। व्यापारियों ने जीपीओं स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर कैण्डिल जलायीं और सहायता राशि जमा की। उधर निर्दल शिक्षक संघ के नेता एमएलसी जगेन्द्र स्वरूप, एमएलसी रायबहादुर सिंह चंदेल व माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एमएलसी चेतनारायण सिंह के साथ वरिष्ठ शिक्षक नेता महेन्द्रनाथ राय ने एक माह का वेतन उत्तराखण्ड राहत कोष को दिया। गोमती नगर के पत्रकारपुर चौराहे, हनीमैन, कठौता चौराहे पर लगे सहायता शिविर में जहां बड़ों ने खाने-पीने की चीजें, कपड़े व पैसे दिए वहीं विराट खण्ड कालोनी के छोटे-छोटे बच्चों ने भी अपने- माता-पिता के साथ जाकर कोष में पैसे डाले। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मण्डल ने राहत सामग्री भेजा। ट्रक को महापौर डा. दिनेश शर्मा एवं संगठन के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने झण्डी दिखाकर रवाना किया। संगठन के लखनऊ प्रभारी देवेन्द्र गुप्ता ने बताया कि एकत्र सामान व धनराशि को ट्रक के साथ जा रहे संगठन के लोग देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जिम्मेदार लोगों को सौपेंगे।

बहराइच की घटना सपा सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र

लखनऊ, (अरविन्द):केन्द्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने बहराइच में हुई घटना के लिए सपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। घटना को सरकार का सुनियोजित षडयंत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र कलंकित हुआ है। बताते हैं कि सोमवार को बहराइच में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित बेनी प्रसाद वर्मा की सभा में सपाइयों ने जमकर बवाल किया था। सपा पर विकास कार्यों में बाधा डालने को आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस प्राकर से विरोध करने का कोई स्थान नहीं हैं। उन्होंने प्रशासन पर भी घटना के दौरान मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। राजधानी में आयोजित पत्रकार वार्ता में क्षेत्र में जमकर विकास कराने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्य में विकास कार्य ठप्प होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बिजली का जबरदस्त संकट है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 50 सीटों पर विजयी होने का दावा करते हुए इस्पात मंत्री ने कहा कि सपा लोकसभा चुनाव में साफ हो जाएगी।

लखनऊ में सपा के प्रदेश कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुनते सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा।(छाया: पंजाब केसरी)

उत्तराखंड की मदद के लिए अधिकारियों से की अपील

लखनऊ,(असलम सिद्दीकी): मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से उत्तराखण्ड की दैवी आपदा के परिप्रेक्ष्य में त्रासदी से निपटने के लिए आर्थिक सहयोग देने की अपील की है। प्रदेश के समस्त प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को आज भेजे गए अपने पत्र में मुख्य सचिव ने कहा है कि विगत दिनों उत्तराखण्ड में भूस्खलन तथा बाढ़ के चलते भारी तबाही हुई है। वहां बड़ी संख्या में लोग इस त्रासदी का शिकार हुए हैं। अत: उत्तराखण्ड में पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। ऐसे में उत्तराखण्ड के लोगों की मदद के लिए अधिकारी/कर्मचारी अधिक से अधिक (कम से कम एक दिन का वेतन) आर्थिक सहायता मुहैय्या कराने का प्रयास करें। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में भूस्खलन तथा बाढ़ में फंसे हुए हजारों लोगों की सहायतार्थ 25 करोड़ रुपये की सहायता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा पहले ही निर्गत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी/कर्मचारी अपना सहयोग 'मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष' में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सुनील कुमार पाण्डेय, उपसचिव, मुख्यमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ को भेज सकते हैं। यह धनराशि मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष के खाता संख्या 1378820696 सेण्ट्रल बैंक, कैण्ट शाखा, लखनऊ में सीधे भी जमा की जा सकती है।

चार दर्जन अफसरों से सीबीआई करेगी पूछताछ

लखनऊ,(असलम सिद्दीकी): उत्तर प्रदेश में हुये एनआरएचएम (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) घोटाले की जांच कर रही सीबीआई चार दर्जन से अधिक अफसरों के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर पूछताछ की तैयारी कर रही है। एनआरएचएम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को इलाहाबाद, वाराणसी, सुल्तानपुर, चंदौली, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, शाहजहांपुर, बांदा, झांसी, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, गोण्डा, आगरा, बलरामपुर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, चित्रकूट व मैनपुरी आदि जिलों में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी मिली है।

इन जिलों में आरोप है कि जननी सुरक्षा योजना में लाभार्थियों को लाभान्वित न करके प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा धन का बंदरबांट किया गया है। इसके अलावा एनआरएचएम में विभिन्न योजनाओं के धन हड़पने जैसे गंभीर आरोपों की भी प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं। इन योजनाओं के तहत में शासन ने प्रत्येक गांव के लिए 10 हजार रुपये सफाई, कीटनाशक दवाओं के छिड़काव आदि के लिए दिए थे। यह धनराशि ग्राम प्रधानों और एएनएम के संयुक्त खाते में जमा कराई जानी थी लेकिन तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा यह धनराशि हड़प ली गई। आरोप तो यहां तक हैं कि यह धनराशि प्रभारी चिकित्साधिकारियों के द्वारा सीएमओ के माध्यम से ऊपर तक भेजी गई। कुछ महीने पहले सीबीआई ने दिल्ली, देहरादून, लखनऊ और गाजियाबाद की शाखाओं में 23 जिलों की शुरूआती जांच (पीई) दर्ज की थी। सीबीआई तभी से इन योजनाओं मे हुए घपले के लिए छापेमारी कर रही है।

सीबीआई वर्ष 2005 से 2011 के बीच एनआरएचएम योजना में हुए घपले की जांच में जुटी है। इन योजनाओं में जननी सुरक्षा योजना, नसबंदी कार्यक्रम, टीबी कार्यक्रम, अंधता निवारण, ट्रांसपोर्टेशन, पावल सप्लाई आदि मामले में बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में संभावना है कि शीघ्र ही इन 23 जिलों के चार दर्जन से अधिक अधिकारियों से पूछताछ करेगी।

विभिन्न योजनाओं के धन हड़पने जैसे गंभीर आरोपों की भी प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले

सड़कें होंगी और चौड़ी...

700 करोड़ से सुधरेगी 12 जिला मार्गों की हालत

लखनऊ, (अरविन्द, असलम):उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 12 जिला मार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण संपर्क मार्गों का निर्माण कराने जा रही है। व्यापार विकास प्रबन्धन निधि के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत यह कार्य कराया जाएगा।

योजना के तहत लगभग 251.22 किलोमीटर लम्बाई के विभिन्न 30 कार्यों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य लगभग 48047.79 लाख रुपये की लागत से तथा लगभग 398.52 किलोमीटर लम्बाई के ग्रामीण मार्गों के 223 निर्माण कार्य लगभग 21216.66 लाख रुपये की लागत से कराए जाएंगे।

व्यापार विकास प्रबन्धन निधि बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने यह जानकारी दी और बताया कि प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के प्रमुख/जिला मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के नए कार्यों में आगरा में 3.5 किमी, मथुरा में 8.8 किमी, एटा में 25.5 किमी, फिरोजाबाद 38.45 किमी, बरेली में 10.5 किमी, बदायूं में 9 किमी, महराजगंज में 5 किमी, गोरखपुर में 5.4 किमी, झांसी में 11 किमी, इटावा में 0.7 किमी, कानपुर नगर में 10.4 किमी, लखनऊ में 19.35 किमी, उन्नाव में 12.68 किमी, सीतापुर में 3.19 किमी, खीरी में 17.15 किमी, गाजियाबाद में 2.2 किमी, सहारनपुर में 13 किमी, हापुड़ में 9.6 किमी , बुलन्दशहर में 3.6 किमी, मुरादाबाद में 15 किमी, वाराणसी में 18.3 किमी एवं सन्त रविदास नगर में 9 किमी के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के 30 कार्य शामिल हैं जिनकी कुल लम्बाई 251.22 किमी तथा लागत 48047.79 लाख रुपये होगी।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग के 12 क्षेत्रों में ग्रामीण मार्गों के निर्माण कार्य कराए जाएंगे जिनमें आगरा में 09 कार्य 14.65 किलोमीटर के, इलाहाबाद में 26 कार्य 53.06 किमी, आजमगढ़ में 25 कार्य 34.50 किमी, बरेली में 01 कार्य 1.30 किमी, फैजाबाद में 52 कार्य 112.05 किमी के, गोरखपुर में 72 कार्य 114.51 किमी, झांसी में 03 कार्य 9 किमी के, कानपुर में 02 कार्य 2.10 किमी, लखनऊ में 20 कार्य 32.97 किमी के, मेरठ में 02 कार्य 5.83 किमी के, मुरादाबाद में 02 कार्य 3.05 किमी के तथा वाराणसी में 09 कार्य 15.50 किमी के कुल 223 कार्य, जिनकी कुल लम्बाई 398.52 किमीशामिल है जिनकी लागत लगभग 21216.66 लाख रुपये है।

2013-14 में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत कार्य कराया जाएगा

लखनऊ स्थित विधान भवन के सामने मांगों को लेकर धरना देते आदर्श शिक्षा वेलफेयर एसोसियेशन के सदस्य।(छाया: पंजाब केसरी)

पंजाब केसरी लखनऊ ब्यूरो कार्यालय का पता एस-75, गोल मार्किट, महानगर लखनऊ। फोनः 0522-3071786 फैक्सः 0522-2329530 ,मो.: 08127786786 E-mail:lucknowpk@gmail.com